* 20th Year
* Issue: 108
* 18.08.2026 (TUESDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

झारखंड में जेएसएसी-सीजीएल परीक्षार्थियों के आंदोलन के आगे झुकी सरकार, हेमंत सोरेन ने भर्ती धांधली पर बिठाई सीआईडी जांच

रांची १७/०८ (संवाददाता): रांची में पिछले 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने अज़्यर्थियों की मांगों पर बड़ा फैसला लिया है। मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा समेत उससे जुड़ी सभी परीक्षाओं और उनके परिणामों को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने साल 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने का भी फैसला लिया है। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर बड़ी संज़्या में अज़्यर्थी रांची में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र लंबे समय से धरने पर बैठे थे। इससे पहले छात्रों और मंत्रियों की टीम के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी

थी। अब सरकार के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी का माहौल है। मौजूद जानकारी के अनुसार, मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद छात्रों के पक्ष में यह निर्णय लिया। सरकार ने विवादित एजेंसी से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को तत्काल रोकने के निर्देश भी दिए हैं। इसका असर उन परीक्षाओं पर पड़ेगा जिनके आयोजन या परिणाम में संबंधित एजेंसी की भूमिका रही है।

सरकार ने सिर्फ हालिया विवाद तक खुद को सीमित नहीं रखा है। साल 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की भी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। यह जांच सीआईडी करेगा। सरकार का कहना है कि इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पिछले वर्षों में भर्ती परीक्षाओं के दौरान कहीं नियमों की अनदेखी या किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई।

हेमंत सोरेन ने कहा है कि सीआईडी और विशेष जांच दल की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती कुछ लोगों पर झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और धांधली के आरोपों का भी जिक्र किया। इन मामलों में गिरज़्तारियां होने की जानकारी भी सामने आई है।

इसी बीच रांची में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य के निजी सहायक बीएन राम को गिरज़्तार किया है। यह गिरज़्तारी झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े मामले की जांच के दौरान हुई है। अब इस मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई और तथ्य सामने आने की उज़्मीद है।

गौरतलब है कि सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सेवानिवृज़् न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का भी फैसला किया है। समिति परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की विस्तृत जांच करेगी। सरकार ने जांच प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की बात कही है। वहीं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जिज़्मेदारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ कौशल को दी गई है।

सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी जिक्र किया है। मुज़्यमंत्री का कहना है कि युवाओं के हित में सरकार पहले ही इस संबंध में कानून बना चुकी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरकार के फैसले की जानकारी मिलते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अज़्यर्थियों ने इसे अपने लंबे आंदोलन की बड़ी जीत बताया। हालांकि, अब उनके सामने नई परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल है। सरकार को यह तय करना होगा कि रद्द परीक्षाओं को दोबारा कब और किस व्यवस्था के तहत कराया जाएगा। वहीं, 2014 से अब तक की जांच में ज़्या सामने आता है और नई परीक्षा व्यवस्था कितनी भरोसेमंद बनती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

जेएसएसी घोटाले पर बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर हमला, बोले-सीबीआई जांच से क्यों डर रहे?

रांची १७/०८ (संवाददाता): झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत में जान-बूझकर देरी कर रही है। 17 अगस्त को मरांडी ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है; वह बस बच्चों को टाल रही है। छात्र छ्रष्ट और JPSC परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की ष्टक्चढ्ढ जांच की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं।

उन्होंने बातचीत को बार-बार टालने और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करने को लेकर सरकार की आलोचना की। साथ ही, उन्होंने कहा कि बातचीत तभी हुई जब छात्रों ने राज्य विधानसभा तक मार्च करने जैसे कड़े कदम उठाने की धमकी दी। उसी दिन, आपराधिक जांच विभाग (ष्टढ्ढष्ठ) ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत रांची में छ्वस्स्ष्ट कार्यालय

में छापेमारी की। छ्वक्स्ष्ट-छ्वस्स्ष्ट सुधार मंच ने बताया कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के नए दौर के लिए तय समय पर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचा, लेकिन संबंधित मंत्री वहां नहीं पहुंचे, जिससे बातचीत अधूरी रह गई।

मीटिंग से पहले, प्रदर्शनकारी छात्र कार्तिक सोरेन ने कहा कि सरकार ने सुधारों से जुड़ी हमारी 95त्न मांगें मान ली हैं। जहां तक ??परीक्षा रद्द करने और (ष्टक्चढ्ढ से) जांच की हमारी मांग का सवाल है, तो उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए, हम उसी सिलसिले में वहां जा रहे हैं। देखते हैं ज़्या होता है। हम पहले दिन से ही सकारात्मक रहे हैं। हमें राज्य सरकार से बहुत उज़्मीदें हैं कि वे हमारी मांगें मान लेंगी। हमारी मांगें जायज़ हैं और वे उन्हें ज़रूर मानेंगी।

एक और छात्र, शशांक ने उज़्मीद जताई कि हमें उज़्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को समझेगी और कोई समाधान निकालेगी। हमें सकारात्मक नतीजे की उज़्मीद है। राजेश प्रसाद, जिन्होंने बताया कि छात्र 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके चार साथी भूख हड़ताल पर हैं, ने कहा, ॠछात्रों को 'सत्यमेव जयते' के मंत्र का पालन करना चाहिए। ष्टरू हमारी सामूहिक पीड़ा को समझते हैं, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में वे इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे और कोई समाधान निकालेंगे... मुझे यकीन है कि बातचीत के इस दौर से अंतिम समाधान निकलकर आएगा।

मोदी सरकार का आतंकवाद पर वार: शहजाद भट्टी का नेटवर्क ध्वस्त, १४ से २०० से अधिक आतंकी दबोचे गए

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान स्थित शहज़ाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया है और स्वतंत्रता दिवस से पहले विध्वंसक हमलों की साजिशों को नाकाम कर दिया है। शाह ने %ङ्ग% पर एक पोस्ट में कहा कि 14 राज्यों में चलाए गए समन्वित अभियानों के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े 200 से अधिक लोगों को गिरज़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान आतंकवाद के प्रति सरकार की %ज़ीरो-टॉलरेंस% नीति का हिस्सा थे और इनका मकसद नेटवर्क द्वारा रची गई हमलों की साजिशों को रोकना था।

शाह ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग-अलग जगहों पर समन्वित अभियान चलाकर इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।

गृह मंत्री के अनुसार, अभियानों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की। बरामद सामान में इज़्प्रोवाइज्ड एज़्सप्लोसिव डिवाइस, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैज़्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ष्टष्टञ्जङ्क कैमरे शामिल थे। शाह ने कहा कि इस नेटवर्क को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस का समर्थन हासिल था और यह भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। शाहज़ाद भट्टी नेटवर्क की जांच कई सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। उन पर कथित तौर पर आतंकी भर्ती, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी और हमलों में शामिल होने के आरोप हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान में मौजूद शाहज़ाद भट्टी का संबंध कई आतंकी मामलों से जोड़ा है, जिनमें हरियाणा के सिरसा में महिला पुलिस स्टेशन पर हुआ ग्रेनेड हमला भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के महीनों में कई राज्यों में भट्टी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं।

प्रशांत किशोर ने बिहार विस में ली शपथ, बोले-यह मेरे लिए गर्व की जिम्मेदारी का पल

पटना १७/०८ (संवाददाता): जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार विधानसभा में स्पीकर प्रेम कुमार की मौजूदगी में बांकीपुर विधायक के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सदन में कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, केदार पांडे, राम विलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जैसे लोगों ने सेवा की है, उसका सदस्य बनना मेरे लिए गर्व की बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज और राज्य की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी के कीमती साल समर्पित करने वाले सैकड़ों विधायकों की तरह काम करना उनके लिए एक बड़ी ज़िज़्मेदारी

भी है। किशोर ने 3 अगस्त को ऐतिहासिक चुनावी शुरुआत की; उन्होंने बिहार के प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जीता और क्चछ्वक्क को बड़ा झटका दिया, जिसके पास तीन दशकों से यह सीट थी। उन्होंने 64,151 वोट हासिल करके क्चछ्वक्क के नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। कुमार को 44,827 वोट मिले।यह उपचुनाव इसलिए कराना पड़ा ज़्योंकि क्चछ्वक्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी।

नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान: वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी (क्चछ्वक्क) ने सोमवार को अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। इसमें राजस्थान की पूर्व मुज़्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और क्चछ्वक्क के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पार्टी की 17 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन नियुक्तियों की घोषणा क्चछ्वक्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की और ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। राजे और माधव उन 13 नेताओं में शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूची में उज़राखंड के पूर्व मुज़्यमंत्री तीरथ सिंह रावत,

बैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम नागराजा, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर भी शामिल हैं। बीजेपी ने आठ राष्ट्रीय महासचिवों की नियुक्ति की है। इस सूची में स्मृति ईरानी के साथ-साथ विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब कुमार देब, सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया शामिल हैं। बीजेपी के संगठनात्मक सचिव बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बने रहेंगे, जबकि शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल को राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वंदे मातरम विवाद में फंसी कांग्रेस, सोनिया-राहुल पर अपमान का आरोप, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस शिकायत में कांग्रेस के सीनियर नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ़ स्नढ्ढक्र दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (्रढ्ढष्टष्ट) हेडक्कार्टर में %वंदे मातरम% गाए जाने के दौरान उन्होंने बाधा डाली थी। यह शिकायत 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस हेडक्कार्टर में हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से जुड़ी है। शिकायत के मुताबिक, सोनिया गांधी ने कथित तौर पर ऐसे इशारे किए और वहां मौजूद लोगों से इस

तरह बात की, जिसे शिकायत करने वाले ने राष्ट्रीय गीत को जारी रखने का विरोध माना। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना गया, हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। ये दावे शिकायत का हिस्सा हैं और पुलिस ने इनकी पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस अभी इस शिकायत की जांच कर रही है ताकि कथित तौर पर हुई बाधा के पीछे के हालात का पता लगाया जा सके। यह शिकायत घटना के अगले दिन, यानी 16 अगस्त को दर्ज कराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि %राष्ट्रीय सज़्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026% को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल चुकी है और अब यह लागू हो चुका है।

भाजपा ने लगाया उमर सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप, किया प्रदर्शन

श्रीनगर १७/०८ (संवाददाता): जज़्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस पर चुनावी वादे पूरे न करने तथा बेरोजगारी एवं विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। हाथों में तज़्तियां एवं पार्टी के झंडे लिए भाजपा कार्यकर्ता डोगरा चौक, महेशपुरा और पनतर्थी में एकत्र हुए और अलग-अलग समूहों में शालीमार रोड होते हुए सिविल सचिवालय की ओर मार्च किया। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और जज़्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने किया। इस दौरान नेकां-कांग्रेस गठबंधन के

खिलाफ नारे लगाए गए। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुज़्यमंत्री उमर अज़्दुल्ला के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा शासन में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने नेकां-कांग्रेस सरकार के पुतले भी जलाए। मार्च के मार्गों और सिविल सचिवालय के आसपास पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की बड़ी संज़्या में तैनाती की गई थी। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जज़्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, ''हजारों भाजपा कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और आम लोग नेकां के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर हैं। लंबे अंतराल के बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस कई वादे करके सज़ा में आई। लेकिन अब जब वास्तव में काम करने का समय है तो वे लोगों को गुमराह करने के लिए बार-बार राज्य के दर्जे का मुद्दा उठा रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की उज़्मीदें पूरी करने में विफल रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राज्य के दर्जे के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। सत शर्मा ने कहा कि सरकार जानती है कि जनता उससे सवाल करेगी और उसने नगरोटा तथा बडगाम में हुए उपचुनावों के परिणाम देख लिए हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ''पूरी तरह विफल राजनीतिक दल'' करार दिया और कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि सरकार प्रभावी ढंग से काम करे और पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो भाजपा अपना आंदोलन और तेज करेगी तथा भविष्य में जिला, शहर और स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरोप लगाया कि नेकां के नेतृत्व वाली सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं से निपटने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद सरकार उचित सड़कों, बिजली और पेयजल सहित पर्याप्त नागरिक सुविधाएं उपलज़्ध कराने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेकां सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और उससे अपनी विफलताओं की जिज़्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भी नेकां सरकार पर तीखा हमला बोला और उस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता तथा खराब शासन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने शुरू में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार की लगातार विफलताओं के कारण पार्टी को अपनी लड़ाई सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा।

विविध समाचार

हिमंता विस्वा सरमा का आरोप, पी चिदंबरम शुद्ध नक्सली, कार्यकाल की जांच की मांग

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): असम के मुज़्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बात की जांच की मांग की है कि ज़्या पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने कार्यकाल के दौरान नज़्सलवाद के खिलाफ जानबूझकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यह टिप्पणी 17 अगस्त को चिदंबरम के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद की गई, जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नज़्सल बताया था। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने चिदंबरम के खुद को दिए गए इस नाम की आलोचना करते हुए कहा कि पी चिदंबरम %दिमागी नज़्सल% नहीं, बल्कि पूरी तरह से नज़्सल हैं। अब जब देश के गृह मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने खुद को %दिमागी

नज़्सल% कहा है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि ज़्या उन्होंने देश के गृह मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नज़्सलवाद को खत्म करने के लिए जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हालांकि ग्रामीण इलाकों के जंगलों में हथियारबंद नज़्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन वैचारिक नज़्सलवाद—जिसे दिमागी नज़्सल कहा जाता है—ने संस्थानों, नीति बनाने वाली संस्थाओं और सार्वजनिक व्यवस्था में अपनी जगह बना ली है और देश की तरक्की में बाधा डाल रहा है। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे ऐसी व्यवस्था-विरोधी सोच रखने वाले लोगों की पहचान करें और उन्हें अलग-थलग करें।

पीएम मोदी ने कहा कि सालों से सार्वजनिक जीवन में माओवादी सोच वाले लोग मौजूद रहे हैं; सरकारी समितियों में भी इस सोच ने कई संस्थानों और पहलों को प्रभावित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम हथियारबंद नज़्सल पर काबू पाने और देश को उनसे मुक्त करने में सफल रहे हैं। भले ही ये नज़्सल खत्म हो गए हों, लेकिन %दिमागी नज़्सल% (नज़्सली सोच वाले लोग) मौके की तलाश में हैं, हिंसा के तरीके ढूंढ रहे हैं और देश को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन दिमागी नज़्सलियों की पहचान करने, उन्हें अलग-थलग करने और एक विकसित देश के लिए युवाओं को एकजुट करने की ज़रूरत है।

इसके जवाब में पी. चिदंबरम ने ङ्ग पर पोस्ट किया, मुझे दिमागी नज़्सल% होने पर गर्व है! इसके अलावा, सरमा ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन पर देश का विरोध करने और देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी का व्यवहार यह साफ कर देता है कि अगर कांग्रेस सज़ा में आई तो देश का ज़्या होगा। ये लोग खुलेआम देश-विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, जैसे लोगों को विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाना और देश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए कहना।

दिल्ली आबकारी नीति: हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया को सीबीआई को नई दलीलों पर दिया चार सप्ताह का समय

दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य प्रतिवादियों को चार हज़्ते का समय दिया। यह समय उन्हें सेंट्रल ज़्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (ष्टक्चढ्ढ) की ओर से दायर उस रिविज़न याचिका में अतिरिक्त लिखित दलीलों पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया, जिसमें आबकारी नीति मामले में उन्हें आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब प्रतिवादियों ने ष्टक्चढ्ढ की लिखित दलीलों पर जवाब देने के लिए समय मांगा; उनके वकील का कहना था कि इन दलीलों में नए आधार और तथ्य शामिल थे।

केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि ष्टक्चढ्ढ ने हाल ही में 103 पेज की लिखित दलीलें जमा की हैं, जिनमें कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो मूल रिविज़न याचिका में शामिल नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि इन दलीलों के साथ दो एनेज़्ज़र (अतिरिक्त दस्तावेज़) भी जमा किए गए थे और उन्होंने इस पर जवाब देने का मौका मांगा। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने ष्टक्चढ्ढ की रिविज़न याचिका की स्वीकार्यता को लेकर शुरुआती आपज़ियां उठाईं। दुर्गेश पाठक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने दलील दी कि कोर्ट को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि ज़्या रिविज़न याचिका सही तरीके से तैयार की गई थी और ज़्या यह कानूनी रूप से स्वीकार्य है।

उन्होंने कहा कि यह आपज़ि सिर्फ़ याचिका पर विचार करने के बारे में नहीं थी, बल्कि इस बात पर सवाल उठाया गया था कि ज़्या इसे रिविज़न याचिका माना भी जा सकता है। बेंच ने पहले के एक आदेश का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसी तरह की स्थिति वाले प्रतिवादियों ने पहले भी मामले की सुनवाई की पात्रता (मेंटेनेबिलिटी) पर आपज़ियां उठाई थीं, जिन पर उनके वकील की सहमति से मुज़्य बहस के दौरान विचार किया जाना था।

कोर्ट ने चौधरी को बताया कि ऐसी शुरुआती आपज़ियों पर कब विचार करना है, यह कोर्ट तय करेगा और उन्हें निर्देश दिया कि वे इन आपज़ियों पर पहले विचार करने को कार्यवाही आगे बढ़ाने की शर्त न बनाएं। ष्टक्चढ्ढ ने प्रतिवादियों की आपज़ियों का विरोध किया। बेंच ने शुरुआती आपज़ियों को तो माना, लेकिन कहा कि वह उन पर अलग-अलग सुनवाई नहीं करना चाहती।

इसमें यह भी बताया गया कि कई मौके मिलने के बावजूद, प्रतिवादियों ने ष्टक्चढ्ढ की रिविज़न याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया, बल्कि शुरुआती आपज़ियां उठाते हुए आवेदन दाखिल किए।

वंदे मातरम विवाद पर बोले इमरान मसूद, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को कहा कि वह राष्ट्रगीत का सज़्मान तो करेंगे, लेकिन उसे गाएंगे नहीं। उन्होंने इसके लिए अपने धर्म का पालन करने के संवैधानिक अधिकार का हवाला दिया। उनका यह बयान %वंदे मातरम% के गायन को लेकर मचे विवाद के बीच आया है, जिसमें पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे हैं। %वंदे मातरम% विवाद पर बात करते हुए मसूद ने समाचार एजेंसी ्रहृढ्ढ से कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। यह अधिकार मुझे संविधान ने दिया है। आप मुझसे यह

अधिकार छीन नहीं सकते। लेकिन, मैं इसका (वंदे मातरम का) अपमान नहीं करूंगा। मैं इसे गाऊंगा नहीं, लेकिन इसके सज़्मान में खड़ा जरूर होऊंगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने कभी %वंदे मातरम% नहीं गाया है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब इसे गाया जाएगा तो वह खड़े जरूर होंगे। मसूद ने कहा कि अगर आप चाहें तो %वंदे मातरम% को बढ़ावा दें। इससे मुझे ज़्या फ़र्क पड़ता है? मैं उतना ही करूंगा जितना मैं चाहता हूं, और वही करूंगा। मैंने इसे पहले कभी नहीं गाया है और न ही भविष्य में गाऊंगा। मैं बस खड़ा हो जाऊंगा। मुझे अपने धर्म का पालन करने का संवैधानिक अधिकार है। पहले %वंदे मातरम% का पूरा इतिहास पढ़ें। फिर आकर मुझसे बात करें। पढ़ें कि यह कहाँ से आया, इसे कैसे लिखा गया और ज़्यों लिखा गया। पहले पूरा इतिहास पढ़ें; उसके बाद, मैं आपको यह समझाऊंगा।

यह बयान तब आया जब क्चछ्वक्क ने %वंदे मातरम% विवाद को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के चिज़ौड़गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि शनिवार को कांग्रेस मुज़्यालय में %वंदे मातरम% गाए जाने के दौरान सोनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे रोकने के लिए कहा था। शाह ने कहा कि उनकी (कांग्रेस की) बेशर्मी देखिए। कांग्रेस पार्टी मुज़्यालय में राष्ट्रगीत %वंदे मातरम% गाया जा रहा था। राष्ट्रगीत के दौरान, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से गाना रोकने के लिए कहा। हम सब बस टीवी पर देखते रह गए।

उन्होंने सीधे सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि सोनिया जी, 140 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं। आपने जो पाप किया है, उसे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। सोनिया गांधी ने पहले ही साफ़ कर दिया था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं और वंदे मातरम के गायन को रोकने का उनका कोई इरादा नहीं था।

चिदंबरम के बाद केजरीवाल ने भी खुद को बताया दिमागी नज़्सली, जो लोग विकसित भारत चाहते हैं...

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी (्रक्क) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी (क्चछ्वक्क) और केंद्र सरकार से सवाल करेगा और पूरे भारत में बेहतर सुविधाओं की मांग करेगा, उसे %दिमागी नज़्सल% कहा जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के बयान पर तंज कसते हुए यह बात कही। माइक्रो-ज़्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ङ्ग (पहले ट्विटर) पर एक छोटे से वीडियो में, दिल्ली के पूर्व मुज़्यमंत्री ने कहा कि अगर भगत सिंह और भीमराव रामजी अंबेडकर आज जीवित होते, तो प्रधानमंत्री उन्हें भी %दिमागी नज़्सल% कहते। उन्होंने खुद को भी %दिमागी नज़्सल% बताया और कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है ज़्योंकि वह एक सच्चे देशभक्त हैं।

केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार, %दिमागी नज़्सल% वह व्यक्ति है जो सवाल उठाता है और शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना चाहता है। उनके अनुसार, जो लोग अस्पताल और सड़कों जैसी अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, वे %दिमागी नज़्सल% हैं। जो लोग उनसे और क्चछ्वक्क से नहीं डरते और %विकसित भारत% चाहते हैं, वे %दिमागी नज़्सल% हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ। मैं दिमागी नज़्सल हूँ। ज़्योंकि मैं देशभक्त हूँ। और मुझे इस पर गर्व है। शनिवार को लाल किले की प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बोलते हुए, पीएम मोदी ने %दिमागी नज़्सलियों% की पहचान करने और उन्हें अलग-थलग करने का आह्वान किया - एक ऐसा शज़्द जिसके बारे में उन्होंने ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया। उनकी इस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया; कांग्रेस ने उन पर और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार, केंद्र का विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति दिमागी नज़्सली है। जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी था, तब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें %दिमागी नज़्सली% होने पर गर्व है। उनकी इस टिप्पणी की आलोचना बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 के उस बयान का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने नज़्सलवाद को भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बताया था। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ने दिन में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर %दिमागी नज़्सली% का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। हमें हैरानी है कि इसके 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा है कि उन्हें %दिमागी नज़्सली% होने पर गर्व है... मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ - कौन सही था, डॉ. मनमोहन सिंह या पी. चिदंबरम?

टूटी बैरिकेडिंग, बढ़ती भीड़ और अफ़वाहें... कैसे हुई लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में यह दुखद घटना?

लखीसराय १७/०८ (संवाददाता): बिहार के लखीसराय ज़िले में स्थित प्रसिद्ध ्रह्यद्धशद्मस्रद्धड्डद्व ञ्जद्गद्वश्चद्यद्ग में सोमवार तड़के सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा-अर्चना के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुखद घटना में कम से कम सात महिलाओं की मौत हो गई और कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह बिहार के लखीसराय ज़िले के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ जैसी स्थिति के कारण कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें सभी महिलाएं थीं। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में भीड़ जमा हुई थी।

ज़िला मजिस्ट्रेट (ष्ठरू) शैलेंद्र कुमार के अनुसार, सोमवार होने के कारण मंदिर में पर्याप्त इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन सुबह 6.30 बजे से 6.45 बजे के बीच दो ट्रेनों के आने से भीड़ अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। कुमार ने बताया कि अचानक, भारी भीड़ के कारण एक तरफ की बैरिकेडिंग टूट

गई, जिससे लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े। इसी वजह से यह दुखद घटना हुई जिसमें सात लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार, कुमार ने कहा, श्रद्धालुओं की कतार अशोकधाम हॉल्ट तक पहुँच गई थी। हॉल्ट पर दो ट्रेनें रुकी थीं। अचानक वहाँ बिजली का एक खंभा गिर गया। यह खंभा पुरुषों की कतार के दाईं ओर था। खंभा गिरने पर अफ़वाह फैल गई कि लोगों पर बिजली का तार (लाइव वायर) गिर गया है, जबकि वह केबल वायर था। उन्होंने आगे कहा, इससे बाईं ओर महिलाओं की कतार पर दबाव पड़ा, जिससे महिलाएँ एक-दूसरे पर गिर गईं। इस घटना से हर जगह घबराहट और अफ़रा-तफ़री मच गई, लेकिन प्रशासन और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौजूद थे और स्थिति का जायज़ा ले रहे थे।

अधिकारियों ने कहा है कि घटना के असल कारणों का पता लगाने के लिए गहन जाँच की जाएगी। इस बीच, घायलों को अस्पतालों में ले जाया गया और उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है।

वहीं, मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वे इस घटना से बहुत दुखी हैं और इसे अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि ज़रूरतमंदों को हर संभव मदद पहुँचाई जाए। उन्होंने ङ्ग पर कहा, हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के उचित और जल्द इलाज के लिए प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की शक्ति प्रदान करें।

सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़

किश्तवाड़ १७/०८ (संवाददाता):जज़्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शनिवार सुबह एक बार फिर भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ जिले के डोलगाम इलाके में हो रही है, जहाँ आतंकवादियों के छिपे होने की पुज़्ता जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाया है। किश्तवाड़ का यह इलाका पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बना हुआ है। पिछले 14 दिनों के भीतर इस क्षेत्र में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का यह चौथा आमना-सामना है। सुरक्षा बलों का शनिवार सुबह जज़्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में छिपे आतंकवादियों से फिर सामना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सेना ने बताया कि जमीनी स्तर पर अभियान की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए सभी स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी के साथ समन्वय किया गया। उसने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गयी और अभियान जारी है।पिछले दो हज़्तों में यह चौथी बार है जब इस इलाके में आतंकवादियों से सामना हुआ है।

इसरो-नासा की तीसरी आंख का कमाल, निसार ने बादलों को चीरकर ली तस्वीर

नयी दिल्ली १७/०८ (संवाददाता):नासा ने बताया कि अमेरिका-भारत के एनआईएसएआर पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह से प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन रडार छवि ने दक्षिणपूर्वी लुइसियाना में मिसिसिपी नदी डेल्टा क्षेत्र को कैद किया है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे जटिल भू-भागों में से एक में शहरी क्षेत्रों, आर्द्रभूमि, जंगलों और कृषि भूमि के सूक्ष्म विवरण सामने आए हैं। निसार नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसएआर) का एक संयुक्त मिशन है, जो पृथ्वी विज्ञान और उपग्रह अनुसंधान में अमेरिका-भारत के दीर्घकालिक सहयोग को दर्शाता है। छवि की स्पष्टता इतनी है कि इसमें लेक पोंटचार्ट्रेन कॉज़्वे को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, जो केंद्र के ठीक दाईं ओर दिखाई दे रहा है। ये दोनों पुल लगभग 24 मील, या 39 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो इन्हें जल के ऊपर बना विश्व का सबसे लंबा निरंतर पुल बनाते हैं। निसार में इस्तेमाल ।बैड रेडार माइक्रोवेव तरंगों पर काम करता है। करीब 24 सेंटीमीटर की तरंगें बादलो को बिना किसी रुकावट के पार करती है और नीचे मौजूद जमीन, पेड़ो, इमारतों और पानी की सतह से टकराकर वापस सैटलाइट तक पहुंचती है। इसी डेटा से रंगीन और सटीक नज़्शे तैयार होते हैं। निसार को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था।

विविध समाचार

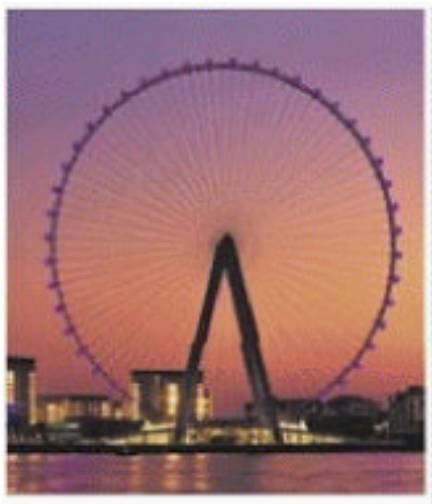

झूले से नहीं लगता है डर, तो एक बार दुनिया के सबसे ऊंचे झूले का लें मजा

क्या आपको झूले पर बैठना पसंद है? क्या आप ऊंचे-ऊंचे झूलों पर बिना डरे झूल सकते हैं? अगर हां, तो दुनिया की सबसे ऊंचे झूले पर एक बार जरूर झूलें। इस झूले पर झूलने से आपकी सांसे और दिल की धड़कनें थम जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अबतक इस झूले पर नहीं झूला है, तो अब आपको दोबारा झूलने का मौका नहीं मिल सकता है। आप में से कई लोग सोच में पड़ गए होंगे आखिर ऐसा क्यों? लेकिन आपको बता दें कि दुबई का सबसे ऊंचा झूला, जिसे आम लोगों के लिए खोला गया था उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। दुबई के इस सबसे ऊंचे झूले को 'दुबई आई' के नाम से जाना जाता है। इसे दुनियाभर के पर्यटकों को लुभाने के लिए काफी ऐतिहासिक तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन अब किसी रहस्यमयी कारणों से इसे बंद कर दिया गया है।

कब हुई थी इस झूले की शुरुआत?

दुनिया का सबसे ऊंचा झूले को रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया है। बता दें कि इस पर्यटक स्थल का उद्घाटन सन् 2021 में किया गया था। यहां के लोगों से इसके बंद होने के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका सही जवाब देने में सफल नहीं हो सका है।

इस झूले को बनाने में लगे 6 साल

दुनिया के इस सबसे बड़े झूले के चारों ओर बेहद की आकर्षक रेस्तां, कैफे, दुकाने और ढेर सारे कर्मचारियों का जमघाड़ा था। इसे बनाने में करीब 6 साल लगे। वहां के आसपास के कर्मचारियों का कहना है कि इस झूले को जब बनाया गया था, तो कहा गया था कि ये सदियों तक चलेगा। लेकिन अचानक से ऐसे बंद होने पर सभी परेशान हैं।

टिकट बूथ पर नहीं आते हैं लोग

बताया जा रहा है कि ये झूला लोगों के लिए लंबे समय तक आकर्षक केंद्र बनकर नहीं रहा। यहां की टिकट बूथ बिल्कुल भी खाली रहता था। झूले के आसपास रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं।

250 फीट ऊंचा है झूला

बता दें कि इस झूले की ऊंचाई लगभग 250 फीट है, जिसमें करीब 48 पॉड्स हैं। इस झूले में एक साथ 1900 बैठकर आराम से झूल सकते हैं। इस झूले को चार पाए वाले स्ट्रक्चर से तैयार किया गया है। बताया गया है कि एक बोइंड 7,7 जंबो जेट के वजन के बराबर है। झूले का कुल वजन 900 टन है। अगर आप दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो एक बार इस झूले के आसपास जरूर जाएं।

चीन की दाओबेइलियांग रोड

चाकू की धार पर गाड़ी चलाना:

दोनों ओर 600 मीटर गहरी चट्टानें, बीच में संकरी

कुछ सड़कें साहस की परीक्षा लेती हैं, लेकिन चोंगकिंग की दाओबेइलियांग रोड तो मानो किस्मत को चुनौती देने जैसी है। यह एक खतरनाक और खतरनाक रास्ता है जिसके दोनों ओर सैकड़ों मीटर गहरी खाइयाँ हैं। दोनों तरफ कोई सुरक्षात्मक दीवार नहीं है, जिससे गाड़ी चलाते समय ऐसा महसूस होता है मानो आप हवा में लटके एक विशाल ब्लेड पर यात्रा कर रहे हों। चीन अपनी इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है जो लगातार दुनिया को आश्चर्यचकित करती रहती है, चाहे वह रातोंरात अस्पतालों का निर्माण करना हो या खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सड़कें बनाना हो। कई बार, ऐसे असाधारण कारनामे केवल चीन में ही संभव प्रतीत होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण चोंगकिंग प्रांत के शिझू में देखा जा सकता है। 'दाओबेइलियांग' स्काई रोड चीनी इंजीनियरों के कौशल और सटीकता का जीता-जागता प्रमाण है। 'दाओबेइलियांग' नाम का अर्थ है 'चाकू की धार', जो इस सड़क के शानदार परिवेश का सटीक वर्णन करता है।

तलवार की धार पर निर्मित

यह सड़क एक बेहद सकरी पहाड़ी चोटी से होकर गुजरती है, जिसके दोनों ओर लगभग 600 मीटर गहरी खड़ी चट्टानें हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जरा सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि पहाड़ी सड़कें तीखे मोड़ों और सीमित दृश्यता के कारण पहले से ही चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन दाओबेइलियांग स्काई रोड को व्यापक रूप से उन सभी में सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है।

एक बेहद विशाल सड़क

लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क की औसत चौड़ाई मात्र 5.5 मीटर है। कुछ जगहों पर यह 3 मीटर से भी कम चौड़ी हो जाती है, जिससे एक समय में केवल एक ही वाहन गुजर सकता है। इसके दोनों ओर कोई सुरक्षात्मक दीवार नहीं है, जिससे ऐसा लगता है मानो आप हवा में लटके एक विशाल ब्लेड पर यात्रा कर रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि यह सड़क पर्यटकों के लिए नहीं बनाई गई थी। इसे एक पवन ऊर्जा कंपनी ने बनवाया था जिसे पवन टर्बाइन लगाने और उनकी मरम्मत करने के लिए किसी पर्वत की चोटी तक पहुंच की आवश्यकता थी। इसका मूल उद्देश्य रोमांच पैदा करना नहीं, बल्कि उपयोगिता प्रदान करना था।

रोमांच के शौकीनों के लिए एक वैश्विक आकर्षण

इसके बावजूद, सड़क की अनूठी बनावट और दिल दहला देने वाले खतरों ने इसे दुनिया भर के साहसिक प्रेमियों और ड्राइवरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। सड़क को दर्शाने वाले दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, और उन्हें देखना ही रोमांच पैदा करने के लिए काफी है। हालांकि इसे रूस की बेबीट रोड जितना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन दाओबेइलियांग स्काई रोड का रोमांच और उत्साह अनुभवी ड्राइवरों को भी डरा सकता है। केवल वही लोग इस यात्रा को करने का साहस करते हैं जिन्हें अपनी ड्राइविंग क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो या जिन्हें ऊंचाई से डर न लगता हो। ऊपर से नजारे बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन सड़क पर सफर करना बेहद रोमांचक है।

दाओबेइलियांग स्काई रोड चीन की सबसे उल्लेखनीय अवसंरचनाओं में से एक है, जो मानवीय साहस और आधुनिक इंजीनियरिंग के असाधारण संगम का प्रतीक है।

यह है दुनिया का सबसे पतला होटल, 9 फीट चौड़ी जगह में बनकर हुआ तैयार

अभी तक आपने होटल को बहुत ही बड़ा और लग्जरियस देखा होगा, लेकिन इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में सलातिगा सिटी स्थित एक होटल पिटुरुम्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये लग्जरियस तो है लेकिन दुनिया का सबसे पतला होटल है। इतना पतला कि यह केवल 9 फीट चौड़ी जगह पर बना है। पांच मंजिल का ये होटल बेकर पड़ी जमीन के टुकड़े पर बनाया गया है जिसका इस्तेमाल लोग पहले डंपिंग ग्राउंड के रूप में कर रहे थे। इस होटल में सात कमरे हैं और इसे दिसंबर 2022 में खोला गया था। हर रूम में डबर बेड, शॉवर और टॉयलेट है। होटल रूम्स के अलावा रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है जहां इवेंट्स और आर्ट एग्जिबिशन होती है।

वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके बर्फीले इलाके के बीच बने इस रहस्यमयी रेगिस्तान की गुत्थी

कारक्रॉस नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान है जिसकी गुत्थी वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं. यह रेगिस्तान कनाडा के युकोन सूबे में है, जो केवल 1 मील एरिया को घेरता है. बताया जाता है कि इस रेगिस्तान के पास एक कारक्रॉस गांव है जहां केवल 301 लोग रहते हैं. वहां के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस जगह को आज तक यहां रहने वाले लोग नहीं समझ सके हैं. उनका कहना है कि क्रॉस रिवर के किनारे कई तरह के दुर्लभ वनस्पतियां है जिनके बारे में आज भी बेहद ही कम लोग जानते हैं. माना जाता है कि सदियों तक किसी को इस इलाके के बारे में लोगों को पता नहीं था. कुदरती तौर पर करीब 4500 साल पहले बैनेट और नारेस झीलें आपस में मिल गई थी, जिसके चलते वहां एक पुल बन गया था. पुल का इस्तेमाल कर लोगों ने पलायन शुरू किया था. जिसके बाद धीरे धीरे यहां कारक्रॉस गांव बसा.

प्राकृतिक तौर पर पुल बनने के बाद कारिबू नाम की जंगली जनजाति का झुंड यहां आकर रहने लगा. साथ ही नताशाहीन नदी के पास शिकार के मकसद से तिलिंगित और ताग्गिश नाम के घुमंतू कबीले रहने लगे. जिसके बाद कारिबू और क्रॉसिंग शब्दों की टोन को मिलाकर इसका नाम कारक्रॉस रखा गया. बताया जाता है कि कारक्रॉस पर जो भी आया है उसने सफेद रंग से सजे पुराने घर, जंग लगी कुल्हाड़िया और सफेद रंग से सजे पुराने घर जरूर देखें होंगे. ये सभी चीजें क्लॉन्डिक दौर की मानी जाती है. ये वो दौर है जब क्लॉसन सिटी और अटलिन के पास लोग सोने की खुदाई के लिये आया करते थे. अब इस वक्त की बात करें तो कारक्रॉस डेजर्ट अब एडवेंचर प्लेग्राउंड में बदल गया है. हर हफ्ते यहां लोग एडवेंचर के लिए आते है. सर्दियों के समय लोग यहां बर्फ का मजा लूटने आते है तो वहीं गर्मियों में बाइक प्रेमियो की संख्या देखने को मिलती है. माना जाता है कि कनाडा के वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए ये एक रिसर्च सेंटर है. ये वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे है कि बर्फीले इलाके में ये एक छोटा सा रेगिस्तान कैसे बना हुआ है. युकोन डियोलॉजिकल सर्वे की भूवैज्ञानिक पनाया लिपॉस्की का कहना है कि कारक्रॉस कुदरत के जरिए बना है. कुदरत की 10 हजार साल की मेहनत का नतीजा माना जा सकता है. 11 से 24 हजार साल पहले विस्कॉन्सिन मैक्रोनेल ग्लेशियर बनने के दौरान ही उत्तरी युकोन में ग्लेशियर जम गया था. उस वक्त कारक्रॉस में एक किलोमीटर की बर्फ जम गई थी. बर्फ के पिघलने पर यहां बड़ी नहर बन गई थी. जिसके बाद ग्लेशियर पिघला और उत्तर-पश्चिम से रेतीली हवाएं चलने लगी जिस कारण ये एक असंभव रेगिस्तान बन गया.

वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि झील सूखने की वजह से ये रेगिस्तान बना जबकि ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि हिम-युग, पानी और हवा ने मिलकर इस उंचाई पर ये अद्भुत रेगिस्तान बना दिया. कारक्रॉस को लेकर एक बात है कि ये जगह आश्चर्य और भय बनाती है. यहां जितना आगे जाना होगा उनका खौफ बढ़ता जाएगा. यहां के पर्यावरण की जटिलता को समझना बेहद ही मुश्किल है लेकिन ये जगह बेहद ही अद्भुत है.

चंदन नहीं ये है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, एक पेड़ ही आपको बना देगा लखपति

दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी की जब भी बात होती है तो अक्सर लोग चंदन की लकड़ी का नाम लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। चंदन दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है। दुनियाभर में सबसे महंगी मिलने वाली लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैक वुड। जी हां, यह लकड़ी चंदन से कई गुणा महंगी है। साथ ही बहुत भी दुर्लभ है। अफ्रीकन ब्लैक वुड इतनी महंगी है कि इसकी एक किलो की कीमत में आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, क्या है ये लकड़ी और क्यों है ये इतनी महंगी। अफ्रीकन ब्लैक वुड एक दुर्लभ लकड़ी है, इसलिए लोगों ने इसका नाम कम ही सुना है। यह लकड़ी भारत में नहीं पाई जाती है। चंदन की लकड़ी की कीमत औसतन जहां सात से आठ हजार रुपए प्रति किलो होती है, वहीं अफ्रीकन ब्लैक वुड की कीमत करीब आठ हजार डॉलर यानी करीब साढ़े छह लाख रुपए प्रति किलो है। ऐसे में ये चंदन से कई गुणा महंगी लकड़ी है। अगर किसी शख्स के पास मात्र एक किलो अफ्रीकन ब्लैक वुड भी है तो भी वह उससे एक कार खरीद सकता है। वहीं अगर किसी के पास इसका पूरा पेड़ है तो आपका करोड़पति होना तय है।

इसलिए बढ़ी इस लकड़ी की कीमत

अफ्रीकन ब्लैक वुड रेयर ट्री है। यह दुनियाभर में मात्र 26 देशों में ही मिलता है। यह पेड़ मूल रूप से तंजानिया जैसे मध्य अफ्रीका के देशों में मिलता है। इसी के साथ सेनेगल पूर्व से इरिट्रिया तक अफ्रीका महाद्वीप के सूखे क्षेत्रों और दक्षिण अफ्रीका के मध्य और दक्षिणी भागों में ये पेड़ मिलते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट होती है। इसके दुर्लभ होने का एक कारण यह है कि यह धरती पर सीमित संख्या में है। ऐसे में यह काफी दुर्लभ है। इस पेड़ को विकसित होने में करीब 60 साल का समय लगता है। सीमित संख्या और अधिक मांग के कारण एक ओर जहां इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी भी बढ़ रही है।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर लग्जरी फर्नीचर तक उपयोग

अफ्रीकन ब्लैकवुड एक अत्यंत कठोर लकड़ी है। यह मजबूत होने के साथ ही स्थिर रहती है, ऐसे में इसपर नक्काशी करना बेस्ट रहता है। यह प्राकृतिक रूप से चिकनी और चमकदार होती है. ऐसे में इसपर पॉलिश आसानी से होती है और पॉलिश से इस लकड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। भारत में इसे सतिसाल कहा जाता है। अफ्रीकन ब्लैकवुड से लग्जरी फर्नीचर बनने के साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं। इस लकड़ी से ओबो, शहनाई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बनाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए मजबूत लकड़ी की जरूरत होती है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

राहुल जेन ज़ी के सबसे करीब

जब से नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद स हाला है (2014), तभी से वे देश की युवाशक्ति को लाभांश यानी डिवडेंड कहते रहे हैं। इसके चलते युवा और छात्र-छात्राएं स्वाभाविक रूप से उनके मुरीद होते गये। उनके तीन बार प्रधानमंत्री बनने के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस विशाल वर्ग को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जोड़ा। नयी पौध को लगा था कि भाजपा सरकार उनकी शिक्षा, रोजगार और उद्यमियता के नये अवसर खोलेगी। हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार, नये विश्वविद्यालय, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया जैसे लुभावने नारे देकर कुछ समय तो मोदी उन्हें रिझाने में कामयाब रहे पर देश में पिछले पांच दशकों के दौरान की सबसे बड़ी बेरोजगारी, बंद होते स्कूल, बदहाल विश्वविद्यालय, लीक होती परीक्षाओं जैसे कारणों से छात्र और युवा वर्ग इस कदर निराश है कि पिछले कुछ समय से देश के ज्यादातर राज्यों में छात्र और युवा सड़कों पर हैं। वे बेहतर शिक्षा व्यवस्था तथा रोजगार की मांग कर रहे हैं. वैसे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर देश की बिगड़ती हालत की तरफ़ लोगों का ध्यान काफी पहले ही खींचा था, जब उन्होंने सित बर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। सरकारी एजेंसियां ज़्यादा जानें प्रचार अभियान और चुनाव डेमोग्राफ़िक्स अखबार कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से लेकर कश्मीर के श्रीनगर तक उनकी पैदल यात्रा वैसे तो भाजपा-संघ द्वारा फैलाई जा रही नफ़रत के खिलाफ़ थी, परन्तु उस दौरान अपने संवाद के जरिये वे देश की केवल सामाजिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भी लोगों को आगाह करते रहे। उन्होंने बताया था कि मोदी सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों, खासकर नोटबन्दी, जीएसटी आदि के कारण बंद होते व्यवसायों एवं उद्योगों से फैली आर्थिक मंदी से बेरोजगारी की विकट स्थिति बनी है। इसके पहले कोविड-19 के समय ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि देश में बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है जिससे बेरोजगारी फैलेगी। उनकी बात का भाजपा और उसके समर्थकों ने मज़ाक उड़ाया था पर उनकी आशंका सही साबित हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की छवि को व्यापक रूप से सुधारा था। इसके बाद उनकी दूसरी यात्रा (पूर्व से पश्चिम) से पूरा देश उन्हें ग भीरता से सुनने लगा। देश उस नरेटिव से बाहर निकलने लगा, जो भाजपा-संघ पोषित आईटी सेल और सा प्रदायिक व जातिवादी समर्थकों ने मिलकर गढ़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सदस्य सं या लगभग दोगुनी हो गयी तथा मोदी एवं भाजपा के सहयोगी दलों से मिलकर बना एनडीए उस 400 के पार नहीं जा पाया, जिसका दावा बढ़ा-चढ़ाकर हो रहा था। भाजपा की सरकार तो बनी पर 240 के अंकों के साथ; वह भी दो दलों की बैसाखियों के बूते। इसके बाद राहुल और कांग्रेस के तेवर संसद के भीतर-बाहर कुछ ऐसे आक्रामक रहे कि मोदी सरकार को अक्सर बैकफुट पर जाना पड़ा। इसका कारण है कि वे मोदी सरकार की खामियों को बेखौफ़ गिनाते रहे- फिर चाहे वह भाजपा-संघ का सा प्रदायिकता का एजेंडा हो या सरकार के सबसे करीबी गौतम अडाणी व मुकेश अंबानी को मिलता संरक्षण। आर्थिक बदहाली के उनके उठाये मुद्दों का सीधा स बन्ध बेरोजगारी से रहा। इस स्टैंड से देश के छात्रों एवं युवाओं में राहुल के लिये खास जगह बनी। इस बीच हुए कई विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और वे शिक्षित युवाओं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं समेत सभी वर्गों की रोजी-रोटी के सवाल उठाते रहे। यहां तक कि उनकी जातिगत जनगणना की मांग का भी सीधा नाता ओबीसी वर्गों के लिये नौकरियों से था जिसे अंततः केन्द्र सरकार को माननी पड़ी। मई के पहले ह ते में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उसे लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने ही विभिन्न राज्यों में आंदोलन चलाये। जून में जब इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की एंट्री हुई तो यह मुद्दा अधिक गरमा गया। कहने को तो तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया गया पर वहां राहुल की नैतिक उपस्थिति इस कदर हावी थी कि सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल करने वाले पर्यावरणवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एवं उनकी पत्नी गीतांजलि को मलाल रहा कि राहुल गांधी उनका उपवास तुड़वाने नहीं आये।

पूर्वोत्तर भारत पर बांग्लादेश की धमकी-खोखली धमकियां, या कुछ और?

आशीष विश्वास

प्रधानमंत्री के तौर पर, हसीना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को अलग-थलग करने के अलावा, बांग्लादेश के अंदर आम लोगों के बीच बढ़ते अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उन्होंने हिफाजत-ए-इस्लाम (एचआई) जैसे नए उभरते हुए संगठनों को बढ़ावा दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बीएनपी को हराने के लिए एक छड़ी की तरह किया!

बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा भारत के पूर्वोत्तर इलाके के सात बहनी राज्यों को छीनने का नारा नई दिल्ली के लिए कितना गंभीर है? भारत के लिए इससे जो राजनीतिक चुनौती खड़ी होती है, उसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि की जानकारी का थोड़ा अध्ययनआवश्यक है।

बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रधानमंत्री के तौर पर 2019-24 के कार्यकाल के आखिर में पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्ते फिर से बनाने की कोशिश की। इस बीच, इस्लामाबाद में सत्ताधारी सरकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अपने कमज़ोर गुप्तचर नेटवर्क को बढ़ा रही थी। एक तरह से, पाकिस्तान की पहले से ही पूर्वोत्तर इलाके के पास पकड़ थी। उसकी ताकतवर गुप्तचर संस्था, आईएसआई, ने नेपाल में अपनी मज़बूत मौजूदगी बना ली थी। वहीं पर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की सोची थी और उसे अंजाम दिया गया था। बांग्लादेश ने तुर्की के साथ अपने राजनयिक रिश्ते भी बेहतर किए थे, जो कश्मीर पर भारत के साथ अपने विवाद में पाकिस्तान का लगातार समर्थक रहा है। अंकारा और ढाका के बीच रिश्ते करीबी थे, क्योंकि दौरे पर आए तुर्की के प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों ने बांग्लादेश में हथियार बनाने के केन्द्र बनाने का सुझाव दिया था।

इस बीच, अपने बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग (एएल) अपने कथित भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खराब रिकॉर्ड की वजह से अपनी ज़मीन खो रही थी, जिससे पश्चिम उससे अलग-थलग पड़ गया था। अवामी लीग को भारत को छोड़कर, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम समर्थन मिला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) वगैरह जैसी विरोधी ताकतों के आंदोलन और ज़्यादा जोरदार होते जा रहे थे, जिससे उन्हें और समर्थन मिल रहा था।

प्रधानमंत्री के तौर पर, हसीना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को अलग-थलग करने के अलावा, बांग्लादेश के अंदर आम लोगों के बीच बढ़ते अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। उन्होंने हिफाजत-ए-इस्लाम (एचआई) जैसे नए उभरते हुए संगठनों को बढ़ावा दिया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बीएनपी को हराने के लिए एक छड़ी की तरह किया! उसमें भारत में अकाली दल को दबाए रखने के लिए जे.एस. भिंडरावाले के उग्रवादी सिखों का समर्थन करने के लिए दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की झलक थी !साफ़ है, सुश्री हसीना ने श्रीमती गांधी की दुखद मौत में छिपे कड़वे राजनीतिक संदेश को गलत समझा- राजनीतिक कट्टरता के साथ खिलवाड़ करने की अदूरदर्शी नीति धर्मनिरपेक्ष सत्ताधारी पार्टियों के लिए लंबे समय तक काम नहीं आई।

बांग्लादेश में पहले से ही संकेत बुरे थे- शेख हसीना और अवामी लीग के लिए, 5 अगस्त, 2025 से बहुत पहले से। हिफ़ाज़त समर्थक तत्वों ने अवामी लीग सरकार को प्रमुख जगहों से धर्मनिरपेक्ष थीम पर बनी सार्वजनिक मूर्तियों और दीवारों पर बनी पेंटिंग हटाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव डाला। वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र कार्यकर्ताओं के बीच बड़े पैमाने पर फैले हुए थे, जिससे अवामी लीग से जुड़ी छात्र लीग के लिए खतरा पैदा हो गया।एचआईऔर जेईआईके कट्टरपंथी युवाओं ने 2021 में ही बांग्लादेश में अपने नए हासिल किए गए दबदबे का संकेत दे दिया था। उन्होंने लगातार दो दिनों तक बहुत ज़्यादा हिंसक भारत विरोधी प्रदर्शन किया, जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तय प्रोग्राम कम करने पड़े। जहां तक अवामी लीग की बात है, तो जिन्न बोतल से बाहर निकल चुका था। भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश पुलिस, उसकी रैपिड एक्शन बटालियन या बीजीबीगार्ड्स की लाचारी को सामने ला दिया था। इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार को भी अपने बढ़ते दबदबे के बारे में बताया। हैरानी की बात है कि ढाका में भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को जो सार्वजनिक तौर पर बुरा-भला कहा गया, उस पर भारत सरकार की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आयी।

बांग्लादेशी विश्लेषकों ने बताया कि ढाका और जिलों में उभरते युवा नेताओं से मिलने वाले पाकिस्तानी एजंटों ने खुलेआम अपना काम बहुत अच्छे से किया। बांग्लादेश में भारत के पूरे दबदबे को पहली बार चुनौती दी गई थी और नई दिल्ली कुछ खास नहीं कर सकी।

पीछे मुड़कर देखें तो, ढाका और नई दिल्ली दोनों जगह के नीति बनाने वालों को बांग्लादेशी युवाओं में इस्लामी कट्टरता के तेज़ी से बढ़ते खतरे के सामने उनकी लापरवाही और नाकाबिलियत के लिए बुरा-भला कहा जा सकता है। उन्होंने एशिया और अफ्रीका में उभर रहे नए बड़े राजनीतिक रूझान को नज़र अंदाज़ कर दिया, जिसमें छात्रों और युवाओं ने दूसरे देशों में पश्चिम-प्रायोजित %कलररेवोल्यूशन% में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे एक के बाद एक सत्तारूढ़ सरकारें गिरीं। सत्तारूढ़ पार्टियों के लिए आधारभूत लाइन यह है कि उन्हें राजनीतिक अतिवाद के साथ कोई तालमेल नहीं करना चाहिए, जो ज़्यादातर अपने प्रायोजक को ही खा जाता है।

हालांकि, यह नहीं मान लेना चाहिए कि बांग्लादेश में डॉ. यूनुस और नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियों के रूप में सामने आए नए भारत विरोधी नेताओं और संगठनों ने अपनी मौजूदा शक्ति पहले ही मज़बूत कर ली है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को काटने और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करने के बारे में उनकी सभी भड़काऊ बातों के बावजूद, भारत के सामने उनकी कोई खास ताकत नहीं है, भले ही वे पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। यह ज़रूरी है कि अब तक चीन द्वारा %सात बहनी राज्यों को आज़ाद करने% की बांग्लादेशी अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है। रूस का कहना है कि बांग्लादेश के साथ संबंध पहले की तरह ही जारी रहेंगे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी ब्लॉक के देशों की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आयी है। खास बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर भी किसी बड़े नेता या पार्टी ने भारत से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को अलग करने की यूनुस की मांग पर टिप्पणी करने की ज़हमत नहीं उठाई है। दुनिया के बाकी हिस्सों से इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी को देखते हुए, यह लगता है कि भारत सरकार को यूनुस की हरकतों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है।

पूर्वोत्तर भारत के बड़े छात्र और युवा संगठन, जैसे एएएसयू, खासी स्टूडेंट्स यूनियन, एनईएसओऔर एजेवाईसीपी, हमेशा बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का विरोध करते रहे हैं। वे बांग्लादेश से घुसपैठ के खिलाफ बड़े आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं।

इसलिए, सही दस्तावेज के साथ भारत (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है!) में यात्रा करने वाले बांग्लादेशियों को छोड़कर, यह कहना गलत नहीं होगा कि संदिग्ध गैर-अप्रवासी बांग्लादेशी आम तौर पर यहां के आम लोगों में शक और अविश्वास पैदा करते हैं,जिसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मु य सलाहकार डॉ. यूनुस को ध्यान रखना चाहिए।

विचार बनकर बने रहते हैं लोग

सर्वमित्रा सुरजन

दिल्ली समाचार विनोद चाचाजी दुनिया भर में स मानित हुए, उनकी रचनाओं के कई भाषाओं में अनुवाद हुए, फिल्में बनीं, साहित्य उत्सवों में उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा, इतनी लोकप्रियता, शोहरत के बावजूद वे जितने सहज बने रहे, उतनी ही सहजता और सरलता सुधा चाची में बनी रही। परंपरागत भारतीय गृहिणी की तरह अपने पति का हर कदम, हर मोड़, हर सुख-दुख में उन्होंने साथ दिया। फिल्म मशाल में दिलीप कुमार और वहीदा रहमान विनोद और सुधा के किरदारों में थे, फिल्मी पर्दे की ये जोड़ी चर्चा में आई तो ललित जी ने हंसते हुए कहा था कि हम तो विनोद और सुधा की इस जोड़ी के प्रशंसक हैं।

वह आदमी नया गरम कोट पहिनकर चला गया विचार की तरह। रबड़ की चप्पल पहनकर मैं पिछड़ गया। ऐसी असाधारण पंक्तियां और ऐसा ढेर सारा असाधारण गद्य, पद्य, कविताएं, कहानियां, उपन्यास और बाल साहित्य लिखने वाले विनोद भाई अब नहीं रहे। ललित सुरजन (मेरे पिता) उन्हें हमेशा विनोद भाई कहकर ही पुकारते थे। घर में हमेशा उनके लिए यही संबोधन सुना। हालांकि हम जब उनसे मुखातिब होते तो उन्हें चाचाजी कहकर ही संबोधित करते और उनके बच्चे भी ललित जी को चाचाजी कहकर ही पुकारते। उनके न रहने पर बचपन की बहुत सी धुंधली स्मृतियां लौट रही हैं।

विनोद चाचाजी मोटर साइकिल पर आया करते थे, शायद राजदूत मोटरसाइकिल होती थी उनके पास। आधी बांहों का शर्ट, पतलून और पैरों में वही रबड़ की चप्पल, जिसका जिक्र ऊपर की पंक्ति में है। रबड़ की चप्पल पहनकर पिछड़ने की बात असल में उस साधारण आदमी का दर्द है, जो गांधी के दर्शन में आखिरी पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है। कई बार उसे ये चप्पल भी नसीब नहीं होती। ऐसे ही किसी दुखी हताश व्यक्ति के लिए उन्होंने लिखा कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था व्यक्ति को मैं नहीं जानता था हताशा को जानता था इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया मैंने हाथ बढ़ाया मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ मुझे वह नहीं जानता था मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था संवेदनशीलता के साथ साधारण व्यक्तियों के मर्म को छूते हुए विनोद चाचाजी अपने हाथ बढ़ाते रहे, कलम चलाते रहे। उनके न रहने पर सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, उनकी पंक्तियों को उद्धृत किया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई दिग्गजों ने हिन्दी साहित्य में उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। यह सब देखकर आश्वस्ति होती है कि हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों, लेखकों की कद्र समाज में अब भी बाकी है। अच्छे साहित्य को पढ़ना, उस पर मनन करना भले कम हो गया हो, या केवल ड्राइंग रूम में सजाने के लिए किताबें खरीदी जाती हों, लेकिन एक कालजयी रचनाकार की दुनिया से विदाई पर अगर उसकी रचनाओं के साथ उसे याद किया जा रहा है, तो यह सही मायनों में कलम की जीत है।

हालांकि कई बार सरकारें, राजनेता अपनी छवि निखारने के लिए लेखकों का इस्तेमाल करते हैं। विनोद चाचाजी के साथ शायद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी। राज्योत्सव के लिए लगे मेले में मु यमंत्री अजित जोगी और विनोद कुमार शुक्ल दोनों अपनी नयी किताबों को हस्ताक्षर के साथ पाठकों को देने के लिए उपस्थित थे। मु यमंत्री के हाथों से पुस्तक लेने, उन्हें अपनी वफादारी दिखाने और तस्वीर खिंचवाने के लिए तो उनके समर्थकों की लंबी लाइन बनी थी, और विनोद भाई के हाथों से किताब लेने वालों की लाइन छोटी थी। यह देखकर अफसोस हुआ था कि मानव मन की जटिलताओं के महीन से महीन रेशे को पकड़ने वाले विनोद कुमार शुक्ल राजनीति के इस जटिल खेल को क्यों कर न समझ सके। खैर इसमें उनकी नहीं राजनीति की बुराई है।

फिर उसी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ती हूं, जिस पर सवार होकर विनोद चाचाजी घर आया करते थे। खाने की मेज़ पर या चाय पीते-पीते बाबूजी और ललितजी के साथ दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी। अमेरिका, ब्रिटेन की राजनीति से लेकर साहित्यिक गतिविधियों पर, एक से बढ़कर एक उ दा विचार हमें सुनने मिला करते। इन चर्चाओं में प्रभाकर चौबे, हरिशंकर शुक्ल, बच्चू जांजगिरी आदि भी अक्सर हुआ करते थे। खैरागढ़ से अगर रमाकांत श्रीवास्तव आते तब भी ऐसी अनौपचारिक साहित्यिक-वैचारिक गोष्ठियां जम जाया करती थीं। और कई बार ये सब लेखक मित्र एक-दूसरे की रचनाओं के विश्लेषण करते, शीर्षकों पर चर्चा करते जो हास-परिहास करते थे, वह भी इतना स्तरीय होता था कि एक अच्छी हास्य रचना तैयार हो जाए। अपनी खुशकिस्मती समझती हूं कि अपने पिता और बाबूजी के साथ-साथ इन तमाम लेखकों-विचारकों से भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के संस्कार मिले। हर वक्त के अपने तकाजे और जरूरत होती है, लेकिन कुछ चीजों के लिए लगता है कि वक्त बदलना नहीं चाहिए। आज घरों में अमूमन ऐसा माहौल कम हो चुका है या लगभग गायब ही है, जहां मां-बाप और उनके मित्रों के साथ बच्चों को अच्छी बातें सुनने-समझने का मौका मिले। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, स्मार्ट फोन ने उनकी नजरों पर डाका डाल दिया है, ऐसी शिकायत तो सुनने मिलती ही है, लेकिन हकीकत ये है कि नासमझ बच्चों की तरह खुद को समझदार कहने वाले अभिभावक भी अपना अधिक से अधिक वक्त स्क्रीन पर बिताने लगे हैं, जिससे बच्चों के साथ उनका संवाद कम हो रहा है और वो बच्चों में उस संवेदनशीलता को संप्रेषित ही नहीं कर पा रहे हैं, जो उन्हें एक बेहतर इंसान और भावी नागरिक बनाए। यहां फिर विनोद चाचाजी का जिक्र करूंगी, जिन्होंने नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, जैसा गंभीर लेखन किया तो उतनी ही गंभीरता से बच्चों के लिए कविताएं, कहानियां लिखीं। छोटे-छोटे वाक्य, रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, बच्चों के विचार फलक पर उभरते दृश्य, उनकी कल्पनाएं, सबको बखूबी अपने लेखन से बांधा। एक बानगी देखिए टेढ़ा मेढ़ा नक्शा टेढ़े मेढ़े द्वीप टेढ़े मेढ़े समुद्र टेढ़ी मेढ़ी नदियां इधर उधर तक फैला ओर छोर आकाश टेढ़े मेढ़े होंगे उसके कोर किनार टेढ़ा मेढ़ा है सब चार दिशा दस कोनों के कहीं कम नहीं अनंत छोटी बच्ची का सब गढ़ा हुआ कहता था एक बूढ़ा संत बड़ों की संवादहीनता का शिकार बच्चे अगर विनोद कुमार शुक्ल की बाल रचनाओं को पढ़ें तो लगेगा कि घर का कोई बुजुर्ग उन्हें अपने पास बिठाकर उनके मन की बात सुन रहा है, अपने मन की बात कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेकर गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप (मध्य प्रदेश शासन), रज़ा पुरस्कार (मध्य प्रदेश कला परिषद), राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त स मान (मध्य प्रदेश शासन), हिंदी गौरव स मान (उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश शासन) के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए 2023 का पेन/नाबोकोव पुरस्कार भी मिला। वे भारतीय एशियाई मूल के पहले लेखक थे, जिन्हें इस स मान से नवाजा गया था। करीब 28 साल पहले 1997 में जब विनोद जी को दयावती मोदी पुरस्कार मिला था, तब देशबन्धु को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मैं तो हमेशा पुरस्कार से अपनी तरफ से बचने की कोशिश करता हूं। पीछे बैठा होने के बावजूद लोगों की नजर उस तरफ घूम जाती है, तो संतोष होता है। यानी बड़े से बड़े पुरस्कार को भी उन्होंने सहज भाव से ही लिया। उनका कहना था कि ऐसा समाज हो जहां कविता की पुरस्कारों से पहचान बनती हो। जहां कवि की पहचान बाद में हो तो कविता के लिए ऐसा पुरस्कार मान्य होना चाहिए। ज़्यादा जानें सहकारिता पर किताबें ई-पेपर सदस्यता समाचार संग्रह शिक्षा से संबंधित सेवाएं यात्रा और पर्यटन पैकेज साहित्य और कविता संग्रह बॉलीवुड समाचार पत्रिका प्रादेशिक समाचार हिंदी भाषा के कोर्स खेल जगत की खबरें विनोद चाचाजी दुनिया भर में स मानित हुए, उनकी रचनाओं के कई भाषाओं में अनुवाद हुए, फिल्में बनीं, साहित्य उत्सवों में उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा, इतनी लोकप्रियता, शोहरत के बावजूद वे जितने सहज बने रहे, उतनी ही सहजता और सरलता सुधा चाची में बनी रही। परंपरागत भारतीय गृहिणी की तरह अपने पति का हर कदम, हर मोड़, हर सुख-दुख में उन्होंने साथ दिया। फिल्म मशाल में दिलीप कुमार और वहीदा रहमान विनोद और सुधा के किरदारों में थे, फिल्मी पर्दे की ये जोड़ी चर्चा में आई तो ललितजी ने हंसते हुए कहा था कि हम तो विनोद और सुधा की इस जोड़ी के प्रशंसक हैं। 2005 में ललितजी की पहल से चौबे कॉलोनी महिला मंडल ने तेजस्विनी स मान का आयोजन किया था। इसमें उन महिलाओं को स मानित किया गया, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपने पति या बच्चों को शोहरत की बुलंदी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सुधा शुक्ल यानी सुधा चाची को भी यह स मान मिला, जिन्होंने विनोद कुमार शुक्ल के लेखन को निर्बाध जारी रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया। कई साल पहले शायद 80 के दशक के आखिरी सालों में विनोद कुमार शुक्ल ने अपने हाथों से एक कविता लिखकर ललित जी को दी थी, जिसे उन्होंने बाकायदा फ्रेम करवा कर अपने द तर में लगा कर रखा और अब तक वह उसी तरह वहां लगी हुई है। नश्वर काया को छोड़कर जाने वालों के बाद ऐसी ही यादें बची रह जाती हैं। विचार की तरह लोग चले जाते हैं, लेकिन विचार बनकर हमेशा हमेशा के लिए यादों में बने भी रहते हैं।

विविध समाचार

जिम ट्रेनर से हुआ पत्नी को प्यार, पति को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी ने बुलाए भाड़े के शूटर

अम्बाला १७/०८ (संवाददाता): हरियाणा के पानीपत के बराड़ा मर्डर केस में बड़ा खुलासा सामने आया है जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में है। इस मामले में सामने आया कि ढाई साल पहले विनोद का मर्डर सुपारी देकर करवाया गया था। जिसमें उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए इस सनसनीखेज वारदात में शामिल थी। पुलिस टीम ने आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11ध्12 की मार्केट से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह स्वीकार लिया और कई खुलासे किए। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने पुलिस को बताया, साल 2021 में वह पानीपत की एक जिम में ट्रेनिंग देता था। विनोद की पत्नी निधि भी वहां एक्सरसाइज करने के लिए आती थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। विनोद को उन दोनों के बारे में पता चला गया तो उसकी एक दो बार कहासुनी भी हुई। विनोद घर पर अपनी पत्नी निधि ा के साथ भी झगड़ा करने लगा। बाद में उसने और निधि ने विनोद की एक्सीडेंट में हत्या करवाने की साजिश रची। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया पूछताछ में आरोपी सुमित उर्फ बंटू ने बताया, वह जानकार ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक निवासी भटिंडा से मिला और उसको 10 लाख रुपए नकद और घर का सारा खर्च देने का प्रलोभन देकर वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया। सुमित ने देव सुनार को पंजाब नंबर की एक लोडिंग पिकअप गाड़ी दिलवाई। देव सुनार ने 5 अक्टूबर 2021 को जान से मारने की नीयत से उक्त गाड़ी से सीधी टक्कर मारकर विनोद का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट मे विनोद की मौत नहीं हुई तो बाद में दोनों ने पिस्तौल से विनोद को मरवाने का प्लान बनाया। देव सुनार की जेल से जमानत करवाई और उसको दोबारा से तैयार कर अवैध हथियार उपलब्ध करवा माफी मांगने के बहाने विनोद बराड़ा के घर भेजा। इसके बाद 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार ने घर में घुसकर पिस्तौल से विनोद बराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी सुमित उर्फ बंटू जेल में बंद देव सुनार के केस और घर पर परिवार का पूरा खर्च खुद दे रहा था। प्लान के अनुसार, निधि मार्च 2024 में अदालत में अपनी गवाही से मुकर गई। पुलिस कप्तान ने बताया कि पुलिस ने आरोपी निधि को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने सुमित उर्फ बंटू के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकार कर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी देव सुनार पानीपत जेल बंद था। पुलिस की ओर से कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका था और मामला ट्रायल पर था। इसी बीच बीते दिनों पहले मृतक विनोद बराड़ा के भाई का वॉटसअप पर एक मैसेज आया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भाई ने मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्तता होने का संदेह जताया। इसको गंभीरता से लेते हुए सीआईए थ्री प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौपी गई। जिसके बाद पुराने राज को फिर से खंगाला गया और गहनता से जांच की गई। जिसके बाद आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

खुशखबरी, सरकार ने बिजली बिल पर मंथली रेंट किया खत्म, केवल यूनिट के देने होंगे पैसे

हरियाणा १७/०८ (संवाददाता): सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि जितने यूनिट बिजली खर्च होगी, उतना ही बिल आएगा। इस तरह मंथली मिनिमम चार्ज को समाप्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब प्रदेश में जिन लोगों के घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हुए हैं, उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट का ही बिल भरना होगा। इस फैसले से राज्य के करीब साढे 9 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होने वाला है। अब तक उपभोक्ताओं से बिजली विभाग प्रति किलोवाट 115 रुपये मासिक शुल्क के रूप में वसूल रहा था। खर्च हुई यूनिट के पैसों के साथ यह शुल्क जुड़ने से बिल बढ़ जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। इस योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाने हैं। इससे ये लोग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादक और उपयोगकर्ता दोनों बन सकेंगे। साथ ही, इस पहल से बिजली बिल भी कम होगा। सरकार ने ये भी फैसला किया है कि जो लोग 10 यूनिट से 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उन्हें सिर्फ 200 रुपए ही देने होंगे। अगर पंजाब की बात करें तो वहां जून के 15 दिनों में बिजली की खपत 2023 की इसी अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत बढ़ गई है। इस साल अब तक पंजाब की अधिकतम मांग 15775 मेगावाट हो गई है। पिछले साल जून के पहले 15 दिनों में अधिकतम बिजली की मांग 11309 मेगावाट और धान के मौसम में 23 जून को 15325 मेगावाट थी। पंजाब राज्य में धान की खेती के कारण आने वाले दिनों में अतिरिक्त कृषि भार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बिजली की स्थिति बेकाबू हो सकती है। एआईपीईएफ ने पहले भी प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मांग की है कि भीषण गर्मी के मौजूदा हालात में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

पंजाब में गहराया बिजली संकट, बदला जा सकता है दफ्तरों का समय

पटियाला १७/०८ (संवाददाता): पंजाब में बढ़ती गर्मी के कारण पारा 44 डिग्री के पार चला गया है तो वहीं अब प्रदेश के लोगों को लंबे बिजली कटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्ज फेडरेशन ने राज्य में गंभीर हो रही बिजली की उपलब्धता व आपूर्ति की स्थिति पर चिंता जताई है। जिसको लेकर फेडरेशन की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि "पंजाब राज्य में, 2023 के दौरान इसी अवधि की तुलना में 1 से 15 जून, 2024 के बीच बिजली की खपत में 43: की वृद्धि हुई है, जबकि अधिकतम मांग जून 2023 में 11309 मेगावाट से बढ़कर जून 2024 में 15775 मेगावाट हो गई है। पूरे पंजाब राज्य में धान की खेती के कारण जून के अंत तक अतिरिक्त कृषि भार बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बिजली की असहनीय स्थिति पैदा हो सकती है।" "महोदय (पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिक्र करते हुए), एआईपीईएफ आपको भारत का सबसे कुशल और जनहितैषी मुख्यमंत्री मानता है और इसलिए आपसे अनुरोध करता है कि आप हमारे उपरोक्त पत्र में सूचीबद्ध बिजली खपत को नियंत्रित करने की पहल का नेतृत्व करें। हमारी राय में, यदि नीचे दोहराए गए इन कदमों को तुरंत लागू नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी।" फेडरेशन का कहना है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो ग्रिड में गड़बड़ी की पूरी संभावना है और लोगों को बिजली से कई दिन वंचित भी रहना पड़ सकता है। फेडरेशन ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बिजली की मांग नियंत्रित करने के लिए कोई कदम न उठाने पर भी चिंता जताई है। इसके साथ ही फेडरेशन ने राज्य में बिजली चोरी पर चिंता जता सरकार को सुझाव दिया है कि बिजली चोरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज करें। बता दें कि 2023 में अधिकतम मांग 11,309 मेगावाट थी। अब वह 15,775 मेगावाट है। धान की रोपाई शुरू होने से बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। राज्य में बिजली की मांग बढ़ने से कट भी लग रहे हैं। यहां तक कि कई जगह तो आठ घंटे तक के कट भी लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि आने वाले समय में लोगों को आठ घंटे से भी ज्यादा लंबे कटों का सामना करना पड़ सकता है और यह संकट कई दिनों तक रहने का भी अनुमान है।

पंजाब में बिजली की खपत में रिकॉर्ड 43 फीसदी की वृद्धि

चंडीगढ़ १७/०८ (संवाददाता): सीवियर हीटवेव के बीच धान का सीजन शुरू होने के चलते पंजाब में जून माह में बिजली की खपत में रिकॉर्ड 43 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। हालात यह हैं कि जून 2023 में जहां बिजली की अधिकतम मांग 11309 मेगावाट दर्ज की गई थी, वहीं इस बार 15775 मेगावाट दर्ज की गई है। इसमें आने वाले दिनों में और वृद्धि होने की आशंका है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने अंदेशा जताया है कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में ग्रिड पर लोड बढ़ जाने से पंजाब ही नहीं, पूरे देश में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए फेडरेशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पंजाब में दफ्तरों के समय में बदलाव करते हुए इसे सुबह सात बजे से दोपहर 2 बजे करने का सुझाव दिया है। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे के मुताबिक दफ्तरों के साथ–साथ शापिंग माल व दुकानों को भी शाम सात बजे तक बंद कराया जाना चाहिए। साथ ही उद्योगों पर पीक लोड प्रतिबंध लगने चाहिए। सबसे अहम पहल पर सेंटर पूल से पंजाब के लिए अतिरिक्त 1000 मेगावाट बिजली का प्रबंध किया जाए।

सीएम मान का बड़ा फैसला, डीसी दफ्तरों में शुरू होगी सीएम विंडो

करप्शन होने पर डीसी व एसएसपी पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ १७/०८ (संवाददाता): पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि समूह डिप्टी कमिश्नर अपने–अपने जिलों के सरकारी दफ्तरों में आम लोगों को किसी भी तरह की असुविध ा और परेशानी के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। यहां डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को साफ–सुथरा, जवाबदेह और प्रभावशाली प्रशासन मुहैया करवाना राज्य सरकार का फर्ज है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ही सबसे कारगर भूमिका निभा सकते हैं जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं निर्विघ्न तौर पर मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों का यह फर्ज बनता है कि वे यह यकीनी बनाएं कि उनके सम्बन्धि ात जिलों के लोगों को सरकारी दफ्तरों का दौरा करते समय किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस काम में ढील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसी किसी भी लापरवाही के लिए सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर को जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर जिले में 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' स्थापित करने का नवीन प्रयास लेकर आ रही है जिससे लोग इस सहायता केंद्र के द्वारा सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'मुख्यमंत्री सहायता केंद्र' पर एक समर्पित अधिकारी उपस्थित रहेगा जो आम लोगों के रोजमर्रा के प्रशासकीय कामकाज के साथ सम्बन्धित आवेदन–पत्र प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के प्रशासकीय कामों सम्बन्धी आवेदन–पत्र सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा जिससे काम को तुरंत पूरा किया जा सके। इसी तरह राज्य सरकार से सम्बन्धित कामों को मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा जायेगा जिनके हल के लिए इन आवेदन–पत्र को प्रशासनिक विभागों के पास भेजा जायेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 'चीफ मनिस्टर डैशबोर्ड' जिले भर में आम लोगों से उनकी अर्जियाँ और बकाया कामों के बारे फीडबैक लेने के साथ–साथ समूची गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के रोजमर्रा के कामों को समयबद्ध और तुरंत पूरा करने को यकीनी बनाऐगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस डैशबोर्ड की नियमित तौर पर निगरानी करेंगे जिससे यह निश्चित बनाया जा सके कि लोगों को अपने आम प्रशासनिक कामकाज के लिए किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट तौर पर कहा, ''यह सही मायनों में पंजाबियों की सरकार है क्योंकि पंजाब के लोगों ने जबरदस्त जनादेश देकर मुझ में विश्वास जताया था जिससे उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यह यकीनी बनाऐगी कि आम लोगों के सभी कामकाज बिना किसी देरी से किये जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नवीनतम तकनीक को अपनायेगी जिससे सरकारी अधिकारियों का अपने दफ्तरों में उपस्थित होने और लोगों को सेवाएं प्रदान करना निश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में विध ायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों की शमूलियत को भी बढ़ाया जायेगा जिससे वह प्रशासन और पंजाब सरकार के दफ्तरों के साथ तालमेल करके लोगों के कामों को पूरा कर सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अलग– अलग गाँवों का एक कलस्टर बनाया जायेगा जहाँ प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय विधायक और जन प्रतिनिधियों के साथ इन गाँवों में जाकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करेंगे जिससे लोगों को कामों के लिए इधर–उधर भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा क्योंकि ' सरकार तुहाडे द्वार' प्रोग्राम के द्वारा सरकार लोगों के दर पर पहुँच जायेगी और यह यकीनी बनाऐगी कि आम लोगों के कामों को प्रमुखता दी जाये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से दफ्तरों में पूछताछ और जांच केन्द्रों के रूप में विशेष काउन्टर स्थापित किये जाएंगे, जिससे लोगों को उस दफ्तर का तुरंत पता लग सके कि उनका काम कहाँ से होना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे लोगों के समय और ऊर्जा की बचत होने के साथ–साथ उनके काम को समयबद्ध ढंग के साथ करना यकीनी बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने धान के सीजन के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी मुहैया करवाने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद किसानों की तरफ से नहरी पानी की योग्य प्रयोग को यकीनी बना कर भूजल के गिर रहे स्तर को रोकना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज भूजल को बचाने की सखघ्त जरूरत है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मॉनसून के आगामी सीजन में बाढ़ की रोकथाम की तैयारी का जमीनी स्तर पर जायजा लेने के लिए वह व्यापक स्तर पर दौरे करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका दौरा घग्गर नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आसपास होगा।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, मंगलवार 18 अगस्त 2026

ओडिशा में हाथियों की संख्या लगभग स्थिर: आवास और मानव-हाथी संघर्ष बना बड़ी चुनौती

भुवनेश्वर १७/०८ (संवाददाता): ओडिशा में हाथियों की आबादी फिलहाल लगभग स्थिर बनी हुई है, लेकिन इन विशाल वन्यजीवों के संरक्षण के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। राज्य में हाथियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित प्राकृतिक आवास उपलज़्ध कराना तथा मानव-हाथी संघर्ष को कम करना वन विभाग और संरक्षण एजेंसियों के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2024 में की गई हाथियों की गणना के आंकड़ों से राज्य में हाथियों की संज़्या में बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिले हैं।

2024 की गर्मियों में हुई हाथियों की गणना में ओडिशा में कुल 2,098 हाथी दर्ज किए गए थे। इसके बाद सर्दियों में की गई गणना में इनकी संज़्या बढ़कर 2,103 हो गई। दोनों आंकड़ों में केवल पांच हाथियों का अंतर है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य में हाथियों की आबादी मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती हाथियों के लिए पर्याप्त प्राकृतिक आवास और सुरक्षित गलियारों को बनाए रखना है।

हाथियों के लिए जंगल केवल रहने की जगह नहीं होते, बल्कि उनके भोजन, पानी और प्राकृतिक गतिविधियों का आधार भी होते हैं। जैसे-जैसे जंगलों के आसपास मानवीय गतिविधियां बढ़ती हैं, हाथियों के पारंपरिक आवागमन वाले रास्तों पर दबाव बढ़ता है। इसका सीधा असर मानव-हाथी संबंधों पर पड़ता है और कई इलाकों में दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। ओडिशा में हाथियों की मौजूदगी कई वन क्षेत्रों में है। हाथी भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाजाही करते हैं। यदि उनके पारंपरिक रास्तों में बाधा आती है तो वे मानव बस्तियों, खेतों और अन्य आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने के साथ लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

मानव-हाथी संघर्ष का एक बड़ा कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास में बदलाव और उनके आवागमन के मार्गों पर बढ़ता दबाव माना जाता है। जंगलों के आसपास कृषि क्षेत्र और अन्य मानवीय गतिविधियां बढ़ने से हाथियों के लिए उपलज़्ध क्षेत्र प्रभावित होता है। भोजन और पानी की तलाश में हाथियों के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने की घटनाएं इसी दबाव का हिस्सा हो सकती हैं। गणना के आंकड़े जहां हाथियों की आबादी के स्थिर रहने की तस्वीर पेश करते हैं, वहीं यह भी संकेत देते हैं कि केवल संज़्या स्थिर रहना पर्याप्त नहीं है। हाथियों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए उनके प्राकृतिक आवास की गुणवज़ा और क्षेत्रफल को बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही ऐसे वन गलियारों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, जिनसे हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकें।

हाथियों की गणना वन्यजीव संरक्षण की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे राज्य में हाथियों की कुल संज़्या और उनके वितरण के बारे में जानकारी मिलती है। समय-समय पर होने वाली गणना के आंकड़ों की तुलना करके आबादी में बदलाव की स्थिति को समझा जा सकता है। 2024 के आंकड़ों में गर्मी और सर्दी के बीच मामूली अंतर सामने आया है, जो व्यापक रूप से स्थिर आबादी की ओर संकेत करता है। विशेषज्ञों के लिए अब चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि स्थिर आबादी भविष्य में भी बनी रहे। इसके लिए जंगलों में भोजन और पानी के प्राकृतिक स्रोतों को मजबूत करना, हाथियों के आवास को सुरक्षित रखना और उनके पारंपरिक गलियारों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना महत्वपूर्ण हो सकता है। मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी अहम है। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को हाथियों की गतिविधियों और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने के तरीकों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। समय पर सूचना मिलने से ग्रामीण हाथियों के झुंड से दूरी बना सकते हैं और टकराव की संभावना कम की जा सकती है। किसानों के लिए फसल नुकसान भी एक बड़ी चिंता है। हाथियों के खेतों में पहुंचने पर फसल नष्ट होने से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे मामलों में नुकसान का उचित आकलन और मुआवजे की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना भी संरक्षण नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। यदि स्थानीय लोगों को संरक्षण प्रयासों से लाभ और सुरक्षा दोनों का भरोसा मिलता है तो हाथियों के संरक्षण में उनकी भागीदारी मजबूत हो सकती है। हाथियों के संरक्षण के लिए केवल वन क्षेत्र बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। उनके बीच सुरक्षित संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है। यदि अलग-अलग वन क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक संपर्क टूटता है तो हाथियों के समूह छोटे क्षेत्रों में सीमित हो सकते हैं। इससे भोजन और पानी की उपलज़्धता पर दबाव बढ़ सकता है और मानव बस्तियों की ओर उनकी आवाजाही की संभावना भी बढ़ सकती है। ओडिशा में हाथियों की संज़्या के लगभग स्थिर रहने का आंकड़ा संरक्षण के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती बनी रहेगी कि आने वाले वर्षों में आबादी केवल संज़्या के स्तर पर स्थिर न रहे, बल्कि हाथियों को स्वस्थ और सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी मिले। राज्य में हाथियों के लिए सुरक्षित आवास, वन गलियारों का संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष में कमी—इन तीनों क्षेत्रों में एक साथ काम करने की जरूरत है। हाथियों के आवागमन वाले इलाकों की पहचान कर वहां मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करना और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बढ़ाना प्रभावी कदम हो सकते हैं। 2024 की गर्मी और सर्दी की गणना के आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में हाथियों की आबादी में फिलहाल कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है। गर्मियों में 2,098 और सर्दियों में 2,103 हाथियों का दर्ज होना आबादी के स्थिर रहने की ओर संकेत करता है। हालांकि यह स्थिरता तभी लंबे समय तक कायम रह सकती है, जब हाथियों के प्राकृतिक आवास और उनके सुरक्षित आवागमन के रास्तों को संरक्षित किया जाए। इस लिहाज से ओडिशा के लिए आने वाले वर्षों में संरक्षण की प्राथमिकता केवल हाथियों की संज़्या गिनने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके लिए पर्याप्त जंगल, भोजन और पानी के स्रोत, सुरक्षित गलियारे तथा स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा। मानव-हाथी संघर्ष को कम करते हुए दोनों के बीच संतुलन बनाना ही राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में सिंटर प्लांट-1 ने उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया

राउरकेला १७/०८ (संवाददाता): सेल के राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के सिंटर प्लांट-1 ने अपनी स्थापना के बाद से अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान 5,11,262 टन के अपने सर्वश्रेष्ठ सिंटर उत्पादन को रिकॉर्ड करके एक नया मुकाम हासिल किया है। यह आंकड़ा 4,97,233 टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन से ज़्यादा है और इसमें 2.7त्न की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

यह उपलज़्धि विशेष महत्व रखती है ज़्योंकि बरसात का मौसम सिंटर उत्पादन के लिए काफ़ी चुनौतियां पेश करता है। इस अवधि के दौरान, बेस मिज़्स, सिंटर बनाने के लिए आवश्यक मूल कच्चा माल, रॉ मटीरियल हैंडलिंग प्लांट में ओपन-यार्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से हासिल किया जाता है। इसके अलावा, अन्य अवयवों में नमी, जैसे कि चूना और डोलोमाइट फाइन्स, सिंटरिंग प्रक्रिया के दौरान प्रतिरोध को बढ़ाता है और उत्पादन दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

इन परिचालन चुनौतियों के बावजूद, सिंटर प्लांट-1 ने जुलाई के दौरान अपने एबीपी का 102.8त्न और अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान 103.5त्न हासिल किया।सभी संबंधित एजेंसियों के सक्रिय समर्थन के साथ, संचालन, मैकेनिकल और इलेज़्ट्रिकल विभागों के ठोस प्रयासों के माध्यम से उपलज़्धि संभव हुई। परिचालन अनुशासन और निरंतर उपकरण उपलज़्धता के सख्त पालन ने रिकॉर्ड प्रदर्शन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सभी तीनों ज़्लास्ट फर्नेस के संचालन के साथ, सिंटर प्लांट-1 को अपनी इष्टतम क्षमता पर चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। विभाग इस गति को बनाए रखने और आने वाले दिनों में कई और उपलज़्धियां हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा के डीजीपी की नियुक्ति का मामला

भुवनेश्वर १७/०८ (संवाददाता): ओडिशा में नए डायरेज़्टर जनरल ऑफ़ पुलिस को चुनने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका तब दायर की गई जब राज्य सरकार ने सोमवार को जल्दबाजी में 1994-बैच के IPS अधिकारियों संजीव पांडा और यशवंत कुमार जेठवा को एडिशनल डायरेज़्टर जनरल रैंक से DGP रैंक पर प्रमोट कर दिया

यात्रा की गाइड और यात्रा की जानकारी सीनियर वकील पी. चिदंबरम ने याचिकाकर्ता, बालेश्वर जिले के जयंत दास की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस की। भारत के मुज़्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। चिदंबरम ने कोर्ट को बताया कि ओडिशा सरकार ने पहले राज्य के नए DGP के चयन के लिए 11 IPS अधिकारियों की एक लिस्ट यूनियन पज़्लिक सर्विस कमीशन को भेजी थी। UPSC को 7 अगस्त को राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों और कमीशन के बोर्ड के साथ बातचीत के बाद लिस्ट में से तीन अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करना था। हालांकि, चिदंबरम ने कहा कि राज्य सरकार ने लिस्ट वापस ले ली और PSC ने बाद में इसे वापस लेने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार अब UPSC को एक नई लिस्ट भेजने की तैयारी कर रही है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह कदम प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि ष्ठत्नक्क के पद पर नियुक्ति के लिए केवल लेवल 16 कैटेगरी के IPS अधिकारियों पर ही विचार किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि ओडिशा सरकार ने कथित तौर पर सोमवार रात या मंगलवार सुबह, ष्ठत्नक्क-रैंक के एक अधिकारी को प्रमोट करने और उस अधिकारी का नाम क्क्ष्ट की योग्य डायरेज़्टर जनरल-रैंक के अधिकारियों की लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने अप्रैल में क्क्ष्ट को ङ्खक्क अधिकारियों की एक लिस्ट भेजी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया। इसके बाद उसने तीन ष्ठत्न-रैंक और आठ ष्ठत्न-रैंक के ङ्खक्क अधिकारियों वाली एक लिस्ट भेजी।

सीनियर वकील ने कहा कि 7 अगस्त को हुई बैठक में क्क्ष्ट ने राज्य सरकार को केवल ष्ठत्न-रैंक के अधिकारियों की लिस्ट जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस मामले को जनहित से जुड़ा बताया और कहा कि इस मुद्दे पर किसी अधिकारी ने कोई रिट याचिका दायर नहीं की है।

इसके बाद ष्टछ्वद्ध ने पूछा कि ज़्या किसी सरकारी अधिकारी ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम ने जवाब दिया कि संबंधित रैंक के अधिकारी मुज़्य रूप से ष्ठत्नक्क के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता एक पूर्व स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है। ष्टछ्वद्ध ने कहा कि क्क्ष्ट को पता है कि योग्य अधिकारियों की पहचान कैसे करनी है और इस पद के लिए योग्य उज़्मीदवारों को लिस्ट में कैसे शामिल करना है।

कांत ने कहा, अगर कोई ऐसी लिस्ट सौंपी जाती है जिसमें अयोग्य लोग हों, तो क्क्ष्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगा।झ्व इसके बाद चिदंबरम ने तर्क दिया कि ओडिशा सरकार ने ,ष्ठत्नक्क रैंक के अधिकारियों को ष्ठत्नक्क रैंक पर प्रमोट किया था और उनके नाम नई लिस्ट में शामिल किए थे। ऐसा करके, सरकार उन्हें क्क्ष्ट के सामने ष्ठत्नक्क के तौर पर पेश कर रही थी, जो उनके अनुसार कोर्ट के निर्देशों का साफ उल्लंघन था। चिदंबरम ने इस मामले पर बुधवार को सुनवाई की मांग की और ष्टछ्वद्ध इस पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए। हालांकि, मंगलवार देर शाम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बुधवार को सुनवाई के लिए तय मामलों की जो लिस्ट पज़्लिश की गई, उसमें ओडिशा के ष्ठत्नक्क की नियुक्ति से जुड़े मामले का कोई ज़िक्र नहीं है।

गांजा की खेती के लिए खाद का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी

भुवनेश्वर १७/०८ (संवाददाता): कृषि मंत्री सिंह देव ने कहा कि राज्य सरकार ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है कि खरीफ फसलों के लिए बनी खाद को गांजे के खेतों में भेजा जा रहा है।उन्होंने कहा, यह बात सामने आई है कि कुछ खाद डीलर गांजे की खेती के लिए ज़रूरी सामान सप्लाई कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है और जो लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य सरकार यूरिया और डाई-

अमोनियम फॉस्फेट (ष्ठक्क) जैसी ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई में रुकावट के बीच वैकल्पिक खाद को बढ़ावा दे रही है। कृषि विभाग ने हाल ही में ज़िला कलेज़्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसानों को ष्ठक्क की जगह कॉज़्प्लेज़्स खाद और यूरिया के विकल्प के तौर पर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें।,द्यह्यश ऋद्गड्डस्र - हाथ बांधकर पत्नी को तालाब में फेंका, दहेज के लिए हत्या का आरोप केंद्र सरकार भी ष्ठक्क की जगह कॉज़्प्लेज़्स खाद के इस्तेमाल पर ज़ोर दे रही है, जिसकी सप्लाई इस साल ग्लोबल सप्लाई-चेन में रुकावट और खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभावित हुई है। हालांकि सहकारिता मंत्री प्रदीप बल सामंत ने कहा कि राज्य में खाद का कोई संकट नहीं है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लगातार कम दबाव के क्षेत्रों के कारण इस साल हुई भारी बारिश की वजह से खाद की मांग कम रही है। उन्होंने कहा कि धान की रोपाई के बाद मांग बढ़ेगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में दो 'दर्पण' शिविर का आयोजन किया गया

राउरकेला १७/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र में आयोजित लगातार दो 'दर्पण' शिविरों का समापन 13 अगस्त, 2026 को हुआ। इन शिविरों में सेल के विभिन्न संयंत्रों एवं इकाइयों से वरिष्ठि अधिकारियों तथा 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र (बी.एस.पी.), बोकारो इस्पात संयंत्र (बी.एस.एल.), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी.), आई.आई.एस.सी.ओ. इस्पात संयंत्र (आई.एस.पी.), मिश्र धातु इस्पात संयंत्र (ए.एस.पी.), केंद्रीय विपणन संगठन (सी.एम.ओ.), केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सी.सी.एस.ओ.), चंद्रपुर फेरो अलॉयज संयंत्र (सी.एफ.पी.) और निगमित कार्यालय के प्रतिनिधियों शामिल थे। इसके अलावा, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (सी.सी.जी.) के प्रतिनिधियों ने भी शिविरों में भाग लिया।

समापन सत्र के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के मुज़्य महा प्रबंधक प्रभारी (सेवा?), श्री अतिश चंद्र सरकार तथा मुज़्य महा प्रबंधक (एच.आर.), श्री मानस रंजन रथ ने प्रतिनिधियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर राउरकेला इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी तथा बी.सी.जी. के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 'दर्पण' पहल का पूरा नाम 'Driving Advancement by Reimagining Performance Assessment and Nurturing' (निष्पादन के आकलन और विकास के नए तरीकों से तरक्की को बढ़ावा देना) है। इसका उद्देश्य निष्पादन प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और परिणाम पर केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम में स्पष्ट भूमिकाओं को परिभाषित करने, SMART Key Performance Areas (KPAs) को विकसित करने तथा व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निष्पादन में सुधार के लिए मापने योग्यग लक्ष्यों को निर्धारित करने पर जोर दिया गया है।

पहले शिविर का उद्घाटन 10 अगस्त को कार्यपालक निदेशक, एच.आर., श्री तरुण मिश्र द्वारा किया गया था। वहीं, श्रृंखला के दूसरे शिविर का औपचारिक उद्घाटन 12 अगस्त को राउरकेला स्थित इंडो-जर्मन ज़्लब में कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री बिस्व रंजन पलाई द्वारा किया गया। सत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों, प्रतिनिधियों और बी.सी.जी. के प्रतिनिधियों के बीच उपयोगी विचार-विमर्श एवं चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।